'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.03.2015
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, क्लॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 18 ● अंक 8 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 1 से 15 मार्च, 2015

प्रधानमंत्री का सूट

डॉ. उदित राज

प्रधानमंत्री ने एक अच्छा सूट क्या पहन लिया लोगों को विवाद करने का मौका मिल गया। यहां तक कि राहुल गांधी भी इस विवाद में कूद पडे जो कि बिल्कुल अपेक्षित नहीं था। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व, उठने-बैठने, बात-चीत और व्यवहार से जितना समाज प्रभावित होता है, उतना शायद किसी और से नहीं। हमारे समाज में जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, सुविधा होते हुए भी साधारण रहन-सहन व लिबास में रहें तो लोग उसे अच्छा मानते हैं। न चाहते हुए भी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को कुछ न कुछ ड्रामा करने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ लोग ड्रामा करने में माहिर भी हैं। हजारों साल से दलित समाज संसाधनों से वंचित रहा है और उसके उत्थान के संघर्ष करने वाले सामाजिक योद्धा डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सूट, पैंट और टाई पहनते थे। ऐसा इसलिए कि उपेक्षित समाज की मानसिकता में परिवर्तन हो और हुआ भी। इससे प्रभावित होकर दलितों में शिक्षा और सम्मान की भूख जगी।

बहुत ही दुख और हैरानी हुई जब प्रधानमंत्री के सूट की कीमत के बारे में लोगों ने आपत्ति दर्ज की। सवा सौ करोड़ की आबादी और दुनिया की तीसरी-चौथी अर्थव्यवस्था के प्रधानमंत्री के सूट की कीमत की चर्चा हो इससे ज्यादा नकारात्मक सोच किसी और समाज में नहीं हो सकती। मैं हमेशा सोचता रहा कि यदि गांधीजी अर्धनग्न का लिबास न धारण करते तो शायद देश कुछ और प्रगति कर चुका होता। नेता के समर्थक उसको अपना आदर्श मानते हैं और इसलिए जो वह खाता-पीता व पहनता है, उसका अनुकरण होता है। यही वजह रही कि हमारे यहां सामाजिक व राजनैतिक कार्यकर्ताओं की एक धारणा बनी कि वे ज्यादा से ज्यादा साधारण लिबास में दिखते रहे। चाहे जितना बडा संसाधन वाला हो, यदि वह सामाजिक व राजनीतिक जीवन में रहा तो खादी ही पहना। जबकि वही व्यक्ति निजी जीवन में महंगा से महंगा लिबास पहनने में कोई परहेज नहीं करता। हमारा ही एक ऐसा समाज है, जहां पर भीख मांगना सम्मान का कृत्य समझा गया। भीख मांगना कैसे सम्मानित पेशा हो सकता है और यही कारण रहा कि मानसिकता नहीं बन पायी कि हम कसकर मेहनत करें, उत्पादन बढाएं और सुविधाएं बढें। जिन समाजों की ऐसी सोच नहीं रही, उन्होंने अपनी बेहतर जिंदगी के लिए उत्पादन बढाया, तकनीक का विकास किया और ज्यादा से ज्यादा बेहतर जीवन जीने के लिए सुविधाओं का निर्माण किया। कार, ए.सी., टेलीफोन, आदि सैकडों ऐसी सुविधाएं हैं, जो बाहर से हमने लिया है। प्रधानमंत्री द्वारा कोट पहनकर इस उदाहरण से देश और दुनिया को जो संदेश देने की कोशिश की, जाने-अनजाने में जिन्होंने विवाद ख?ा किया, उन्होंने समाज की बहुत क्षति की।

विदेशियों की नजर में भारतीय सपेरे एवं मदारी हुआ करते थे। धीरे-धीरे यह छवि खत्म हुई और अब समय आ गया है कि इस तरह का संदेश दिया जाए कि हम किसी से कम नही हैं। कुछ अपवादों को छोडकर ज्यादातर सर्वहारा का नेतृत्व भी अच्छा से अच्छा लिबास में रहा है। साम्यवादी क्रांति ने दुनिया को बदलकर रख दिया और जो सुविधाएं मालिकों अर्थात् उत्पादन के स्रोतों पर काबिज करने वाले के लिए थीं, वही आम जनता के लिए भी हो। इसका उन देशों के गरीबों की मानसिकता पर बडा प्रभाव पडा और उनके जीवन में भी परिवर्तन आया। कार्लमार्क्स, एंगेल्स और लेनिन आदि के लिबासों को देखकर इसे आसानी से समझा जा सकता है। चीनी क्रांति के अग्रदूत माओत्से तुंग ने भी यही उदाहरण देश के सामने पेश किया। क्यूबा, में क्रांति करने वाले फीडल कास्ट्रो ने भी ऐसा उदाहरण पेश किया। अमरीका की बुनियाद डालने वाले महान नेता जैसे - जार्ज वाशिंगटन और अब्राहम लिंकन आदि भी बेहतरीन सूटेड-बूटेड रहे हैं। एक कुतर्क किया जा सकता है कि यदि जनता गरीब है तो नेता कैसे उससे अलग दिखे। इस कुतर्क का जवाब यह है कि नेता आदर्श होता है और उसका अनुकरण जनता करती है। यदि नेतृत्व अच्छे लिबास में दिखता है तो उसके मानने वाले भी उस दिशा में प्रयास करेंगें, जब प्रयास करेंगें तो मानसिकता में बदलाव आएगा और मानसिकता का भी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में बडा योगदान होता है। बराक ओबामा से बेहतर लिबास अगर प्रधानमंत्री का रहा तो यह हमारे लिए गर्व करने की बात है।

आजादी के बाद जो समाजवादी और साम्यवादी नेता रहे हैं, वे ज्यादा से ज्यादा साधारण लिबास में थे। एक साधारण कुर्ता-धोती या पायजामा में दिखना और झोला लटकाना एक पहचान बन गयी थी। यह ज्यादा मायने नहीं रखता कि ये किस लिबास में हैं, बल्कि इनका आशय शिष्यों और जनता के ऊपर वैसा ही पडा, जैसा ये खुद रहे। इस सादगी की संस्कृति को फटीचरी की संज्ञा दी जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इन्होंने संसाधनों के वितरण की लडाई लडी, लेकिन जिनके लिए किया, उनकी मानसिकता नहीं बदली कि वे ज्यादा मेहनत करें, बेहतर रहें और जो भी सुविधाएं संभव हैं, उसको अर्जित करें। यह भी एक कारण है कि काम करने वाले अधिकार तो मांगते रहे लेकिन अपनी बेहतरी के लिए उत्पादन आदि बढाने की दिशा में शायद ही कोई रूचि रही हो। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इनका शोषण मालिक नहीं करते थे, लेकिन काम करने वाले में वह प्रवृत्ति नहीं पैदा हुई जो दुनिया के और समाजों में है। जापान के मजदूर हडताल या विरोध करने के नाम पर उत्पादन बढा देते हैं, क्या हमारे यहां कभी ऐसा हुआ है ?

मीडिया के डर एवं नकारात्मक सोच रखने वालें की वजह से अब हालात इतने खराब हो गये हैं कि सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं, शादी-विवाह, जन्मदिन या छुट्टी मनाना आदि छुप-छुपाकर करने लगे हैं। अतः दोहरा चरित्र जीने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। अब तो कुछ लोग ऐसा भी करने लगे हैं कि लोगों की आलोचना के डर से चुपचाप कार्यक्रमों को विदेशों में कर रहे हैं। बहुत से लोग जो सार्वजनिक जीवन में हैं, जैसे - विधायक, सांसद, मंत्री, नेता उनके स्टाफ और राजनैतिक गतिविधियों में कितने संसाधन का व्यय होता है, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अगर वही व्यक्ति फटीचर दिखे तो लोग बडा अच्छा मानते हैं, जबकि अच्छे लिबास और रहन-सहन में अन्य खर्चों की तुलना में 2 प्रतिशत भी खर्च न होता हो। जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उनके यहां शादी का कार्यक्रम था और उसमें कतरनी चावल परोसा गया था, उसकी चर्चा दूर-दूर तक हुई। इससे यही लगता है कि बाहरी ताम-झाम में फटीचर दिखो और अन्दर कुछ भी कर लो, लोग खुश होते हैं। प्रधानमंत्री ने सूट या अच्छे कपडे पहने उसकी जितनी ही प्रसंशा की जाए कम है, क्योंकि वे आदर्श हैं और आम जनता इससे प्रभावित होकर बेहतर करना चाहेगी। एक प्रधानमंत्री के लिए महंगे सूट का प्रश्न खडा करने वाला, क्या संदेश देना चाहता है कि देश की जनता फटीचरी की तरफ बढे ?

*****

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का
अखिल भारतीय परिसंघ
एक दिवसीय सम्मेलन

22 मार्च, 2015 (रविवार) को प्रातः 10 बजे
एन.डी.एम.सी. कन्वेंशन सेंटर, संसद मार्ग,
जंतर-मंतर के सामने, नई दिल्ली

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के तत्वावधान में आगामी 22 मार्च, 2015 (रविवार) को प्रातः 10 बजे से एन.डी.एम.सी. कन्वेंशन सेंटर, संसद मार्ग, जंतर-मंतर के सामने, नई दिल्ली पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन को राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. उदित राज जी के अलावा परिसंघ के अन्य प्रमुख नेता सम्बोधित करेगें। परिसंघ के सभी स्तर के पदाधिकारियों व संबद्धित संस्थाओं के पदाधिकारियों से आग्रह है कि वे प्रमुख लोगों के साथ उपरोक्त दिन, दिनांक व स्थान पर पहुंचकर सम्मेलन में शिरकत करें।

शामिल होने की अग्रिम सूचना व्हाट्सअप 9999504477 पर दें तो अच्छा रहेगा, जो लोग स्मार्टफोन और व्हाट्सअप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं वे 09015552266 पर शामिल होने वाले लोगों के नाम, मोबाइल, ई-मेल व पता एस. एम.एस. कर सकते हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति परिसंघ, सम्पर्क : 01123354841-42

नसोसवायएफ ने भोपाल किया धरना प्रदर्शन

धरने में आरक्षित जन समूल का अभिवादन करते हुए डी. हॅ विर्धन दवणेव अन्य नेतागण

नेशनल एस.सी, एस.टी. ओबीसी स्टुडेन्ट एण्ड यूथ फ्रंन्ट (नसोसवायएफ) ने मध्यप्रदेश के छात्राओं को छात्रवास, छात्रवृत्ती और विविध महाविद्यालय में छात्रों की आर्थिक लूट की समस्याओं को लेकर 21 फरवरी 2015 को सुबह 11 बजे नीलम पार्क, जहांगीराबाद, भोपाल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में विविध जिलों के हजारो छात्र और छात्र नेता उपस्थित थे । मध्यप्रदेश के पुलिस प्रशासन के बीच काफी समय तक पुलिस और छात्रों के साथ अनबन चालू थी।

देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा छुआ-छूत पाई जाती है। इस का असर दलित-आदिवासी छात्रों पर भी दिखाई दे रहा है। शहरों में दलित छात्रों को सवर्ण जाति के लोग किराये पर रुम देने से मना करते है। इससे दलित छात्रों की निवास की समस्यायें बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार के द्वारा जो छात्रावास हैं। उन छात्रावासों की स्थिति बहुत खराब है। इस के साथ ही छात्रों की संख्या मे पर्याप्त छात्रावास उलब्ध नही है शिक्षा साल खत्म होने जा रहा है लेकिन अभी तक दलित छात्रों को मिलने वाली छात्रवृती अभी तक मिल नही है।

बहुत से महाविद्यालयों में शक्ती से शिक्षा फीस, परीक्षा फीस मनमानित तौर पर छात्रों से वसूल की जा रही है। और यही महाविद्यालय फिर से छात्रवृत्ती के माध्यम से भी फीस लेते है। यह महाविद्यालय दूसरी तरह फीस की वसूल कर रहा है। दलित-आदिवासी एकमात्र विकास माध्यम शिक्षा है। प्रदेश में दलित-आदिवासी छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते है मगर वहा भी आठवीं कक्षा तक पास करने का जो आदेश निकाला उसे सरकारी स्कूलों में छात्रों को ठीक से पढ़ाया नही जा राहा है और छात्र ठीक से पढ़ाई करता भी नही इससे इन छात्र के भविष्य की समस्या निर्माण हो चूकी है।

इस धरना प्रदर्शन के मुख्य माँगे :-

1. महाराष्ट्र में जो सामाजिक न्याय भवन के द्वारा छात्रावास बनाएं गये, उसी प्रकार मध्यप्रदेश सरकार हर जिले में एक- एक हजार छात्र-छात्राओं को छात्रावास बनाये ।
2. जो छात्रावास वर्तमान में स्थित है उनमे सुधार कर, सुरक्षाकर्मी एवं सफाई कर्मी नियुक्त किय जाये।
3. आठवीं पास का जो सरकार ने अध्यादेश बनाया वह रद्द किया जाये।
4. 2014 मे राज्य सरकार द्वारा छात्रावास के बारे में निकाले गये अध्यादेश को रद्द किया जाये, और सभी छात्रों को छात्रावास में वापिस प्रवेश दिया जाये, एवं आवासीय योजना के तहत लाभ कक्षा 10 वीं से अन्य पाठ्यकर्मो तक दिया जाये ।
5. S.C., ST तथा OBC छात्रों के लिये Help Line नंबर सेवा प्रारंभ की जाये जिससे छात्र अपनी समस्याओं से अवगत कर सके।

ये मुख्यमाँगे लेकर हम नीलम पार्क, जाहिगींराबाद भोपाल में 21 फरवरी 2015 को धरना प्रदर्शन कर रहे है । हम अपील करते है छात्रो से कि बड़ी संख्या मे इस धरना प्रदर्शन मे शामिल होकर अपने अधिकार के लिए संघर्ष करे । इस ये मुख्यमाँगे भोपल के एच.डी.बी. की तरफ से मुख्यमंत्री को दिया है। अगर महीने के भीतर अगर पूरी नही होती है तो हर एक जिलों मे इस का अक्रोश दिखाई देगा

इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व नसोसवायएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी. हर्षवर्धन, राष्ट्रीय समन्वयक प्रताप सिंह अहिरवार, प्रदेशाध्यक्ष सुशिल बरखने, इस धरना को सफल बनाने के लिऐ भोपाल जिला अध्यक्ष बंटी अहिरवार, होसंगाबाद संभाग से मनीष जी, चेतन मण्डलोई, संतोष अहिरवार, प्रकाश अहिरवार, महाराष्ट्र से गणेश येरेकर, बालाजी कोंडामंगल, रवि सुर्यवंशी, राहुल सोनाळे, संघरत्न निवंडगे और अन्य छात्र उपस्थित थे।

***

डॉ. उदित राज द्वारा संसद के चौथे सत्र में उठाए गऐ मुद्दे

During Zero Hours on 24 th February, 2015

दिनांक 24/02/2015

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मै यहां उन लोगों की बात उठाने जा रहा हूं जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं। अगर रिजर्वेशन न होता तो आज भी इनकी हालत नारकीय होती। पोलिटिक्स ओर गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन होने की वजह से इनकी स्थिती थोडी बेहतर हुई है। जामिया मिलिया यूनीवर्सिटी एक नैशनल युनीवर्सिटी है, लेकिन उसने वर्ष 2011 के एडमिशन में रिजर्वेशन लागू करने के लिए डिनाई किया। वर्ष 2014 में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में रिजर्वेशन लागू करने के लिए डिनाई किया। क्या जामिया युनीवर्सिटी को कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट नही मिलती है ? क्या टैक्स पेयर्स की मनी उन्हें नही जाती है ? उन्होंने माईनोरिटी को रिजर्वेशन दिया, यह ठीक बात है। एससी और एसटी के रिजर्वेशन को समाप्त किया गया है ?

अध्यक्ष महोदया, मै आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे। पूरे देश में लेडीज यूनिवर्सिटी बहुत कम है। जामिया यूनीवर्सिटी अच्छी यूनीवर्सिट है। वहां पहले उन लोगों को रिजर्वेशन मिलता रहा है लेकिन अब क्या वजह है कि रिजर्वेशन डिसकन्टीन्यू हुआ है ? मुझे यही पैटर्न अलीगढ मुस्लिम यूनीवर्सिटी में भी देखने को मिला है। मैं अनुरोध करूँगा कि इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!

Under Rule 377 on 24 th February, 2015

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): In the Union budget, a substantial amount of money is allocated under the head of Scheduled Caste Sub Plan and Tribal Sub Plan. There is no effective mechanism to monitor the proper utilization of this money in different schemes. It is a well Known fact that State governments have been diverting and unutilizing the fund. There is departure from the past of disbursement of this fund this year as compared to previous years under the head post metric scholarship scheme, special central assistance to scheduled cast sub plan. girls hostel and boys hostel etc. It is not clear whether the government is going to transfer the moneu to the State/UT or will continue the same method. Furthermore, some of the State Governments are allegedly indulging in anti SC/ST activities. I, therefore, urge upon the Government to ensure proper utilization of funds under the said head.

During Zero Hours on 25 th February, 2015

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Hon. Speaker, thank you very much for giving me this opportunity to raise the problems of rural peopal of my constituency that is situated in Narela. In Narela, the Delhi Development Authority acquired land in 1996 to build sub-city over there. So far not much has been done. Not noly that, integrated fright corridor was to be set up which could have been done very easily. It is connected with road and rail. The only thong is that the warehouses have to built over there. They are there. But the DDA and the Govremment have not taken pain to regularise them. Apart from DDA, in the 2010 Zonal Plan, plans have been made for a number of recreational and educational institutions. But so far land has not been allotted About 1,000 hectares of land were allotted for recreational activities and 500 hectares of land were allotted for recreational activities. But till today, the Ministry of Urban. Development and the DDA has doneany anything. Thousands of flats are lying vacant. They have not been allotted. People are homeless.

If metro is extended to that area, then those houses can be allotted and people will willingly go and occupy those houses. Thank you so much for giving me this opportunity.

During Zero Hours on 27 th February, 2015

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Madam, I thank you for giving me an opportunity to express my observation about the Public Sector Undertaking. public sector undertaking have been called milching cows for the officers in collusion with Politicians also. I would draw your attention to the LIC which comes under the ministry of Finance. LIC is being milked like anything. I am going to highlight four issues. एल.आई.सी. में जो यू.के. की फॉरेन ब्रांच है, वह वॉयबल नही है और यह बडे ऑफिसर्स के टूर का डेस्टिनेशन बन गया है। When that branch is not viable and profit is not coming from them, then it should be wound up.

During Zero Hours on 10 th March, 2015

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, एंटरप्राइजेज में एससी और एसटी का जो पार्टिसिपेशन है, वह बहुत ही कम है। वह पहले 11-12 पर्सेंट हुआ करता था, अब घट कर 9 पर्सेंट के आस-पास हो गया है और दिनों-दिन घटता चला ला रहा है, जबकि रजिस्ट्रर्ड एंटरप्राइजेज केवल 7 पर्सेंट के आस-पास ही हैं। हम आपके माध्यम से एम.एस.एम.ई मिनिस्टर से अनुरोध करेंगे कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए और ज्यादातर ये लोग एपेरल में, लैदर में काम करते है, अनक्लीन और अनहाईजीनिक पेशे मे भी अभी लगे हुए है। इनका रजिस्ट्रेशन भी नही होता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इनका पर्सेंटेज बढाया जाना चाहिए।***

नसोसवायएफ ने किया राज्यस्थान मे धरना प्रदर्शन

नेशनल एस.सी, एस.टी. ओबीसी स्टुडेन्ट एण्ड यूथ फंन्ट (नसोसवायएफ) ने राज्यस्थान के जिला पाली के छात्रों ने हॉस्टल की मांग को लेकर कलक्ट्रेर कार्यालय पर जामकर प्रदर्शन एवं नारेबाजी कर जिला कलक्टेर के नाम एसडीएम विशाल दवे को ज्ञापन सौपा।

संगठन के जिला संयोजक अशोक सिरण ने बतया कि बांगड महाविद्यालय के छात्रावास भवन में वर्तमान

में विधि महाविद्यालय संचलित हो रहा है तथा विधि महाविद्यालय का नया भवन भी तैयार है।

पूर्व मे भी छात्रावास की मांग को लेकर प्राचार्या डॉ. सुशीला राठी को कई बार ज्ञापन दिए, परंतू महाविद्यालय प्रशासन ने छात्रो की एक भी नहीं सुनी, जिससे मजबूरन कॉलेज छात्रों को पढाई छोडकर कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटने पर विवश होना पडा।

इस पर एसडीएम ने छात्रों की मांग का शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया, जब जाकर छात्र शांत हुए।

1. महाराष्ट्र में जिस तरह सामाजिक न्याय भवन के द्वारा छात्रावास बनाएं गये, उसी प्रकार राज्यस्थान सरकार हर जिलें में एक- एक हजार छात्र-छात्राओं को छात्रावास बनाये ।

2. जो छात्रावास वर्तमान में स्थित है उनमे सुधार कर, सुरक्षाकर्मी एवं सफाई कर्मी नियुक्त

3. S.C., ST तथा OBC छात्रों के लिये Help Line नंबर सेवा प्रारंभ की जाये जिससे छात्र अपनी समस्याओं से अवगत कर सके।

4. आठवीं पास का जो सरकार ने अध्यादेश बनाया है वह रद्द किया जाये।

सुरक्षा की चिंता में महिलाओं से छिन रहा रोजगार

नई दिल्ली, 5 मार्च

आर्थिक नरमी के साथ सुरक्षा संबंधी चिंताओं की वजह से पिछले दो साल में उद्योग में महिला कर्मचारी की संख्या कम हुई है। पिछले दो साल में उन क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों की संख्या 26.5 फीसदी घटी है जहां उन्हें रात्रि पालि में काम करना होता है या देर तक रुकना पड़ता है या उनका दफ्तर शहर के बाहरी हिस्से में उद्योग मंडल का अध्यन में बात सामने आई है। अंतराष्ट्रीय महिला दिवस आठ मार्च पर जारी इस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले दो साल में अर्थव्यवस्था में नरमी के साथ महिलाओं को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताओं की वजह से पिछले दो साल में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी कम हुए है। एसोचैम ने इस स्थिति में बदलाव के लिए सरकार और नियोक्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया है। यह अध्यन 20से 50 आयु वर्ग की करीब 1,600 महिलाओं से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। अध्यन को गुरुवार को यहां आम आदमी पार्टी आप के नेता अलका लांबा, स्पाइस ग्रुप की कारपोरेट मामलों की समूह अध्यक्ष प्रीति मल्होत्रा, एस इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ अध्यक्ष व वैश्विक संयोजक प्रीति मेहरा ने जारी किया है। अलका लांबा ने कहा कि दिल्ली को रेप कैपिटल नहीं बल्कि महिलाओं के लिए अनुकूल राजधानी बनाने की जरूरत है। महिलाओं में असुरक्षा की भावना को दूर किए जाने की आवश्कता है। प्रीति महल्होत्रा ने कहा कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित और बेहतर माहौल बनाने की जरूरत है। उनमें कार्यस्थल पर जरूरी विश्वास पैदा किया जाना चहिए।

> जब तक सामाजिक परिवर्तन नही होता तब तक पुरूष की मानसिकता में बदलाव नहीं हो सकता। क्या केवल कानून से महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान संभव है ? कड़े कानूनों का कुछ स्थानों पर दुरूपयोग होता है, उससे लोग भय मानकर महिलाओं से बचते हैं। यह भी एक कारण है कि महिलाओं का रोजगार छिन रहा है।

एसोचैम महासचिव डीएस रावत ने कहा कि महिलाएं घर और बाहर दोनों ही जगहों पर बेहतरीन मानव संसाधन है। उन्हें सुकूल और सुरक्षा दिए बिना देश के जनसांख्यिकीय लांभांश का फायदा नहीं उठाया जा सकता है। एसोचैम की महिला शाखा की तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दो साल में उन उद्योगों और सेवाओं में महिला कर्मियों की संख्या 26.7 फीसदी घटी है जहां उन्हें रात्रि पाली में काम करना होता है या जिनका कार्यस्थल घर से दूर शहर के बाहरी क्षेत्रों में है। अध्यन में शामिल 48 फीसदी महिलाओं का कहना है कि निर्भया कांड के बाद पिछले दो साल के दौरान उनकी चिंता कम होने के बजाय बढ़ी है। सुरक्षा को लेकर दिल्ली-एनसीआर की महिलाओं ने सबसे ज्यादा चिंता जताई। इसके बाद बंगलूरू, मुंबई, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश का स्थान रहा।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के 2012 के आकड़ो के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 14.2 फीसदी के साथ दिल्ली सबसे ज्यादा रहा। बंगलुरु में 6.2 फीसदी और कोलकाता में 5.7 फीसदी अपराध के दर्ज मामले जहां 2001 में 1,43,795 थे, वहीं 2014 में ऐसे मामलों की संख्या 2,80,465 तक पहुच गई। केवल आपरेटर असोसियन की अध्यक्ष रूप शर्मा ने कहा- सरकारी क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र में महिला सुरक्षा को लेकर चिंता अधिक है।

सच्चे अंम्बेडकरवादी ही देश भक्त है

इन दिनो देश में देशभक्ति का माहौल है। सामाजिक एंव राजनैतिक संगठन खुद को देशभक्त साबित करने में लगे है । हमने 2 साल पहले ''इंडिया अगेंस्ट करप्शन'' इस सामाजिक संघठन ने भारत में फैले भ्रष्टाचार और काले धन को लाने की मांग को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया । पिछले 2 साल से देश में सामाजिक और राजनैतिक संगठन ने राष्ट्रध्वज तिरंगा का इस्तेमाल कर के खुद को सच्चा देशभक्त साबित करने में दौड़ लगाई। मगर मैं समझ नही पा रहा हूँ। ये लोग देश में इस भारतीय समाज व्यवस्था में कौन सा कांतिकारी बदलाव और विकास करने की सोच रखते है। न ही इन लोगों में भारतीय संविधान के प्रति प्रेम दिखाई देता है। न इस देश की समाजिक व्यवस्था मे फैले हुए विभक्तावादी समाजव्यवस्था को खत्म करने की बाद दिखाई देती है । लोकतंत्र के उपर पूंजीवाद हावी हो चुका है। पूंजीवाद को नियंत्रित करने की बात ये लोग करते हैं। हमने देखा इन लोगो को खोखले वादे और आकाश मे नंगे नारे, इस देश का मीडिया जो जातिवाद और पूंजीवाद का शिकार हो चुका है। ये मीडिया भी इन लोगों को देशभक्त साबित करने में पूंजीवाद का सहारा लेकर लगा है । ना तो इस मिडिया को प्रतिनिधियों मे ना देशभक्ति दिखाई देती है ना तो मिडिया की विचारधारा न ही उसका इमान।

देशभक्ति एक तो सरहद पर बाहरी दुश्मनों से लड़ने वाले सिपाहियों मे हमे दिखाई देती है। जिनमे पूरे समर्पण और बलिदानों के साथ ये सिपाही बाहरी दुश्मनों से देश की रक्षा करते हैं और दूसरे अंतरिम समस्या, दुश्मनों से और एक सार्वभौम लोकतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए जो प्रयास करते है। वो कार्यकर्ता देशभक्त होते हैं । हमने दुनिया के इतिहास में अमेरिका के अपने लोकतंत्र में आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक लोकतंत्र तथा एक सशक्त राष्ट्र स्थापित करने के लिए अपने देश की अंतरिम समस्याओं से लड़ने वाले लोग और उनका बलिदान हमे याद हैं । अब्राम्हन लिंकन और जॉर्ज कॅनेडिज जसै राष्ट्र अध्यक्ष अमेरिका में निग्रो (काले रंग) की गुलामी की और काले गोरे वर्णभेद के खिलाफ संघर्ष करते हुये अपना बलिदान दिया । वे लोग सच्चे राष्ट्रभक्त थे जिन्होने अमेरिका जैसे राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र बनाने के लिये अंतरिम समस्या के खिलाफ संघर्ष किया। आज अमेरिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लोकतंत्र बहाल है ।

भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। बाबासाहब डॉ.अंम्बेडकर ने एक स्वतंत्र भारत का संविधान जनता के माध्यम से जनता को अर्पित किया है ।

डी. हर्षवर्धन
राष्ट्रीय अध्यक्ष, नसोसवायएफ

संविधान कहता है देश के हर एक नागरिक को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, अवसर को समानता प्रदान करने का

अधिकार देता हैं। उसी तरह देश को एक संघ बनाने का प्रयास भी करता हैं । ये सभी विचार देश में प्रस्थापित करने के लिए जो प्रयास करते हैं उनको हम देशभक्त कह सकते है।

'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' के आंदोलन ने जन लोक पाल का मुद्दा उठाकर आर्थिक भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग की मगर समाज के अंदर ऊँच-नीच और सांस्कृतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ गूंज तक निकाली नही । पूंजीपती या के भ्रष्टाचार से लोकतंत्र खोखला होता जा रहा है । न तो उसके उपर इस आंदोलन के द्वारा कोई टिप्पणी नही हुई। विरोध तो दुसरी तरफ 2014 के चुनाव में आर.एस.एस. जैसे धर्मार्ध संघठन के राजनैतिक दल ने इसी पूंजीवादियों को अपना सहारा बनाकर देशभक्ति का बुर्का पहनाकर सत्ता हस्तगत किया है।

इस संगठनों और राजनैतिक दलों ने जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात की न ही जातिय शोषण और दमन को रोकने की इन संगठनों ने कभी इस देश के दलित और आदिवासियों को सामाजिक न्याय मिलने की बात कही है । आज देश मे विषमतावादी शिक्षा व्यवस्था है । न ही इसको बदलने की बात की ये कैसी खोखली देशभक्ति हैं जो सिर्फ तिरंगा लेकर भारतमाता की जय करके देश भक्त होने का दिखावा कर रहे हैं । यही लोग हैं इस देश में जातिवाद को सहारा दे रहे हैं । जातिय शोषण को मजबूत कर रहे हैं। सांमन्तवाद और पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे है । शिक्षा का बाजारी करण कर रहें है । देश मे धर्माध्यता और धर्म का धंधा चला रहे है

तो दूसरी ओर इस देश के दलित-आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके जाति व्यवस्था का खात्मा करके समतावादी समाज व्यवस्था प्रस्थापित हो, दलित-आदिवासी के शोषण और दमन खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं । सभी को अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए लड़ रहे है। शिक्षा दलित-आदिवासी और गरिबों के विकास का एकमात्र माध्यम हैं उसको समान और अनिवार्य करने की जिद पकड़े हुए हैं । वो लोग जो लड़ रहे हैं देश में फैले हुए धर्मान्तरो से लोकतंत्र पर हावी हो रहे हैं पूंजीवाद से जो विरोध करते हैं । देश के संविधान का सम्मान करते है और खुद को आम्बेडकर वादी कहते हैं। वही लोगों में मुझे सच्ची राष्ट्रभक्ति दिखाई देती है जो देश में एक बड़ा सामाजिक बदलाव चाहते हैं । लोकतंत्र को मजबूत रखना चाहते हैं। यही सोच बाबासाहब डॉ. अंम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखी थी। वो इस देश में जाती विहीन समता मुलक समाज चाहते थे लोकतंत्र से बढ़ कर देश में कोई चीज बड़ी हो नही सकती इस लिए उन्होने पूंजीवाद को नियंत्रित रखने की बात की थी। बाबासाहब डॉ. अंम्बेडकर ने धर्म निरपेक्षता की बात की थी सबको शिक्षा और समान अवसर की बात रखी थी ।

आज उनके विचारों को मानने वाले मिशन के सिपाही ही एक नए और संम्पूर्ण राष्ट्र का निर्माण कर सकते है। हम उनको एक सच्चे राष्ट्र भक्त कह सकते है जो सच्चे अंम्बेडकरवादी है। ये सच्चाई है इसमे कड़वे पन है मगर खोखला पन नही । इमानदारी है मगर बेइमानी नही वही देशभक्ति है।

***

बजट में कटौती

जब दलितों व आदिवासियों का उत्थान तमाम सरकारी योजनाओं के माध्यम से नहीं हो पा रहा था तब 1974 में ट्राइबल स्पेशल प्लान और 1989 में शिड्यूल्ड कास्ट स्पेशल प्लान लाया गया ताकि जो अलग से इनके विकास के लिए राशि रखी जाए, अन्यत्र खर्च न की जा सके। इसमें योजनागत बजट का आबादी के अनुपात में पैसे को अलग रखकर उत्थान करना था। उस समय योजनागत् बजट की राशि ज्यादा होती थी और वह धीरे-धीरे कम होती गयी। शुरु में ही इतना भेदभाव किया गया कि नाम-मात्र की धनराशि अलग की गयी। धीरे-धीरे धनराशि बढ़ी तो जरूर लेकिन कभी भी जितना मिलना चाहिए, उससे आधी ही रही। यह आधा भी ईमानदारी से खर्च नहीं हुआ। इससे समझना कोई मुश्किल नहीं है कि दलितों व आदिवासियों के प्रति जितना अन्याय होता है, उतना शायद किसी और के साथ नहीं। हक मांगने और चिल्लाने से भी नहीं मिल रहा है और ऐसे हालात में बड़ा जन आंदोलन ही करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति/जन जाति परिसंघ की मान्यता है कि किसी और पर भरोसा न करते हुए स्वयं एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए इस वर्ष दस लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राजनैतिक प्रतिनिधि संख्या में थोड़े होने के बावजूद पार्टियों के बिना इजाजत के मुंह नहीं खोल सकते हैं, अतः परिसंघ के बैनर तले ही अधिकार और सम्मान मिल सकेगें। सारिणी में दर्शाया गया है कि कितना बजट में कटौती होती रही है।

इस वर्ष योजनागत् बजट 4,65,277 करोड़ है और अनुसूचित जाति के लिए 30,850 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि 77,235 करोड़ होना चाहिए था। अतः 46,385 करोड़ का हक छीन लिया गया है। इसी तरह से जनजाति का 20,034 करोड़ की कटौती की गयी है। जन जाति को 19,979 करोड़ मिले जबकि 40,013 करोड़ मिलना चाहिए था। पूर्व में भी ऐसा ही होता रहा है। क्या ऐसी समस्याओं का समाधान छोटे-मोटे प्रयास से हो सकता है? पूरी तरह से असंभव है कि जब तक बड़ा आंदोलन न खड़ा किया जाए।

*****

Denied allocation under Union Budget 2013-14- SCSP and TSP

	2013-14		2014-15		2015-16	
	SCP	TSP	SCP	TSP	SCP	TSP
Total Plan Budget	4,19,068.00	4,19,068.00	5,75,000.00	5,75,000	4,65,277.04	4,65,277.04
Allocation to SC/ST outlay	41561.13	24,598.39	50,548.16	32,386.84	30,850.88	19,979.77
Due as per proportion of the SCs @16.6 and STs@8.6%	67,889.02	34,363.58	93,150.00	47,150.00	77,235.99	40,013.83
Denied allocation	26,327.89	9,765.19	42,601.84	14,763.16	46,385.11	20,034.06

Source :Union Budget 2013-1413,Expenditure Vol.I and II

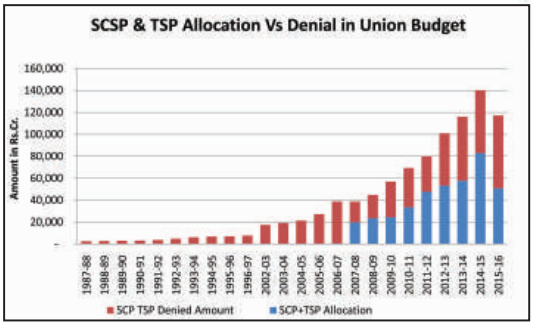

डॉ. उदित राज का संत्रानगरी मे खरी खरी

नागपूर दि.07 मार्च 2015

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉ. उदित राज का संत्रा नगरी नागपुर में नगरागमन दिनांक 7 मार्च शाम के 9 बजे जेट एअरवेज से हुआ। उनके स्वागत के लिए बाबासाहेब अंम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सेकडो कार्यकर्ताओं गुलदस्ते व फुलो के हार लिए तकरीबन एक घंटा पहले से ही उपस्थित थे। परिसंघ के महाराष्ट्र राज्य ईकाई के उपाध्यक्ष श्री विकासदादा तुमडाम ने यह जानकारी देते हुए कहा है की, डॉ. उदित राज शनिवार रात ठिक 9 बजकर 30द मिनिट पर नागपूर हवाई अड्डे पर अवतरित हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद स्वंय अपवनी एकमात्र ब्रीफकेस हाथों में उठाए वे जैसे ही हवाई अड्से बाहर आए जयघोष के नारों से व डॉ.उदित राज जिंदाबाद, उदित राज आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है के नारो से आसमान गूंज उठा। नागपुर शहर अध्यक्ष श्री प्रभुलाल परतेकी, श्री दीपक तभाने, श्री प्रदिप मेंढे, श्री कवडूजी धुर्वे, नागपूर शहर सचिव श्री सिध्दार्थ उके, श्री बबली मेश्राम, आदि कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ते व फुलों के हार से डॉ. उदित राज का स्वागत किया तो परिसंघ के महाराष्ट्र राज्य ईकाई के उपाध्यक्ष श्री विकासदादा तुमडाम ने संपूर्ण नागपूर नगरी के आदिवासी समाज की और से गुलदस्ता देकर डॉ. उदित राज का स्वागत किया।

इसके उपरांत डॉ. उदित राज कार्यकर्तोओ के अनुरोध पर एवं केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितीनजी गडकरी के नागपुर में होने के कारण सीधे महल स्थित गडकरी वाडे की और प्रस्थान कर गए। उनके साथ लंबी कतार में कार्यकर्ताओं के वाहन होने के कारण डॉ. उदित राज का पूरा काफिला नागपुर नगरी व्यस्त सडको से निकलते हुए गडकरी निवास पहुचे श्री गडकरी जी ने गुलदस्ता देकर डॉ. उदित राज जी का स्वागत किया व दोनो नेता आगे की चर्चा के लिए निवास पर एन्यी चेंबर की और निकल पडे।

तकरिबन 1 घंटे की गहन चर्चा के तुरंत बाद रात के भोजन के लिए डॉ. उदित राज जी होटल प्राईट के पास स्थित सुश्री. अर्चना भोयर के निवास स्थान की और प्रस्थान कर गये। वहॉ डॉ. उदित राज के स्वागत के लिए रात 11 बजे भी बहुसंख्या में सीनियर महिला कार्यकर्ता मौजूद थी। इतनी संख्या मे रात 11 बजे महिला कार्यकर्ताओं को इंतजार करते हुए पाने के बाद डॉ. उदित राज जी ने उनका आभार व्यक्त किया तथा उनका स्वागत स्विकार कर दूसरे दिन रविभवन के सभागृह में आयोजित विदर्भस्तरीय पदाधिकारीयों की कार्यशाला में शामिल होने की गुजारिश की।

दूसरे दिन रविवार दिनांक 8 मार्च को सुबह 9 बजे डॉ. उदित राज नागपुर नगरी के पूर्व उपमहापौर श्री संदीप जाधव के निमंत्रण पर उनके घर गये। वहॉ बहुसंख्या में उपस्थित कार्यकर्तोओं के साथ चाय पर उन्हे मार्गदर्शन कर 11 बजे रवीभवन के कॉटिज पर अयोजित प्रेस कॉन्फ्रेरस कों संबोधित करने निकल पडे । नागपुर के लगभग सभी ईलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मिडीया के प्रतिनिधी डॉ. उदित राज जी का इंतजार कर रहे थे। बगैर समय गवाये मिडीया को संबोधित करते हुए कहा की आज दलित समाज की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई हैं अगर ऐसे हि बनी रही तौ वह दिन दूर नही जो बाबासाहब के पूर्व थी और इस स्थिती के लिए बहुतांश दलित नेता ही जिम्मेदार है।

नागपुर सम्मलेन में मंच पर बैठे हुए माननीय डॉ.उदित राज व परिसंघ के अन्य वरिष्ठ नेतागन

दोपहर 12 बजकर 30 मिनिट पर रविभवन के सभागृह में आयोजित विदर्भस्तीय पदाधिकारी की कार्यशाला में सभी 11 जिलो के पदाधिकरी बहुसंख्या में उपस्थित थे । दोपहर 12 बजर 30 मिनिट पर आयोजित कार्यशाला शाम 4 बजे तक चली । परिसंघ की मजबूती के लिए आयोजित इस कार्यशाला में सथी पदाधिकारीयों को पद के अनुरुप जिम्मेदारियॉ सौपी गई व कुछ नई नियुक्तीयॉ भी डॉ.उदित राज जी ने की जिसमें नागपुर जिले के पुर्व अध्यक्ष श्री प्रभुलाल परतेकी को पदोन्नती देकर विदर्भ कार्यकारणी में जिम्मेदारी दी गई तो श्री. दीपक तभाने को नागपुर जिले के अध्यक्ष पदभार सौपा गया। नये सदस्य श्री सुनिल जेकब को विदर्भ कार्यकारणी में स्थान दिया गया । पूर्व अपर पुलिस अधिक्षक श्री इंगले व उनकी डॉ.बेटी तथा सुश्री. अर्चना भोयर, नंदा पाटील ममता गेडाम एवं अन्य नये सदस्यों को परिसंघ में शामिल कर जिम्मेदारी देने की सिफारीश राज्य के अध्यक्ष श्री सिध्दार्थ भोजने से की गई। उसके उपरांत डॉ. उदित राज राज्य के प्रमुख पदाधिकरीयों से राज्य में संगठन की स्थिती और मजबूती की जानकारी ली व परिसंघ के विस्तार हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं सूचनाएं दी ।

इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉ. उदित राज ने अनेक अनछुए पहलुओं को हाथ लगाते हुए काहा कि, आज देश घर वापसी को लेकर इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है। किसकी घर वापसी की जा रही हैं। उन आदिवासीयों की या पिछडे दलित मुलसमानों की जो कभी आपके घर सदस्य थे ही नही और जो थे उन्हो अस्पृश्य कह कर समाज से बाहर रखा जा रहा था ऐसे में घर वापसी के पहले घर दुरुस्ती होनी चाहिए। उसी तरह अनुसूचित जाति/जनजाति को दी जा रही राशी में कटौती का मुद्दा भी उन्होने उठाया ।

महाराष्ट्र राज्य की सरकारी नौकरीयों में व उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति/ जनजाति के आरक्षण में हो रही बोगस आदिवासीयों के घूसखोरी रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर गंभीरता से इस सभा में विचार किया गया। परिसंघ महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष श्री विकासदादा तुमडाम ने कहा है की बोगस आदिवासीयों को रोकना हम सभी का कर्तव्य है ताकी सच्चे आदिवासीयों को उनका अधिकार मिल सके।

इस कार्यशाला की सफलता के लिए राज्य इकाई के उपाध्यक्ष श्री सिध्दार्थ भोजने के मार्गदर्शन में परिसंघ के सर्वश्री सुनील मेश्राम विदर्भ अध्यक्ष, प्रभूलाल परतेकी नागपुर अध्यक्ष, दीपक तभाने, प्रदीप मेंढे ॲड. झांबरे, ॲड. मेश्राम, कवडुजी धुर्वे, विलास मनोहर, गोर्वधन गेडाम, जयराज परतेकी, विलास कुळमेथे, विद्या मस्के नंदा पाटील आदि अनेक पदाधिकारीओं जीतोड महेनत की हैं। ****

भारतीय महिलाओं के मुक्तिदाता बाबासाहब डॉ. अम्बेडकर

भारत की नागवंसी सिंधू संस्कृति बहुत प्राचीन हैं। आज से आठ हजार साल पहले भारत में मातृसत्ताक परिवार पद्धति थी। महिलओं ने खेती की खोज की। उस समय उसमे महिलायें गृह और वैदकीय कार्य में प्रगतिपथ पर थी। शंबर राजा और बली राजा का शासन था। बाद मे आर्य भारत मे बहार से चार हजार साल पहले आये। उनके आक्रमण से भारत कि सभी महिलाये और प्रजा गुलाम बनाये गए। उनको कोई अधिकार नही था। वेदोमे पुरुसुक्त द्वारा वर्ण व्यवस्था का निर्माण कि गई। उस समय सभी महिला और ओ.बी.सी., एस. सी., एस टी, एन टी उनको शुद्र कहा गया। सामाजिक विषमता सब तरफ फैली थी। बाद में आज से ढाई हजार साल पहले भ. बुद्ध, भ. महावीर का उदय हुआ। उन्होने समता का आंदोलन चलाया।

तथागत बुद्ध का उदय

सामाजिक विषमता के खिलाफ भगवान बुद्ध ने जनआंदोलन चलाया। यज्ञ,स्वर्ग, नरक,ईश्वर ,आत्मा, अंधश्रद्धा, वर्ण व्यवस्था आदी बातो को नकार दिया उन्होने स्वत्रांत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय इन महान तत्वो का उद्घोष किया। सभी समाज के महिला और पुरुषों को बुद्ध धम्म में प्रवेश दिया विज्ञानवाद का प्रचार किया। स्त्री के महत्व के बारे में भ. बुद्ध कहते हैं। स्त्री दुनिया कि महानतम विभूती हैं। क्योंकि उसके द्वारा बोधीसत्व और विश्व के अन्य शासक जन्म लेते हैं उन्होंने बौद्ध धर्म में मौसी महाप्रजापति, आम्रपाली, विशाखा, गौतमी, आदि महिलाओं को भिक्षुणी संघ मे प्रवेश दिया। और वे महान भिक्षुणी बन गयी बौद्ध धर्म में जाति नही हैं ये मानवतावाद है। भ. बुद्ध ने सबसे पहले महिलाओं को स्वतंत्रता दी। उस जमाने में उपनिषद भी तयार हुये थे। पतंजली तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के मुताबिक महिलाओं को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार था। गार्गी तथा मैत्रीय ये ऋषी कन्याये ऋषीवो वाद विवाद करती थी। उस समय जाबाला जैसी स्वतंत्र महिला भी थी। उस समय नियोग पद्धती थी पतंजली कहते है कि महिलायें आचार्य भी थी। बौद्ध धर्म का प्रभाव पॉच सौ वर्षो तक रहा।

बाबासाहेब डॉ.अंम्बेडकर कहते है कि ऐसा था फिर भी महिलाओं का पतन क्यों हुआ उनके मुताबिक सम्राट अशोक का नाती बृहदरथ की हत्या उसका पंडित सेनापती पुष्पमित्र शुंगने भरे दरबार मे कपट से की थी और उसके समय मनुस्मृती का काला कानून बनाया गया उसके मुताबिक सभी महिलाये, ओ.बी.सी, एस. सी .एस.टी. एन टी.इनपर ग्यान लेने, अर्थाजन करणे पर बंदी लगाई गयी। उनको वेद मंत्र पढ़ने का, यज्ञ करने का और पिता के संपत्ती में कोई अधिकार नही था। इसलिए बाबासाहेब डॉ.अंम्बेडकर ने मनुस्मृती जलाई इसके लिय बाबासाहब ने हिंदू महिलाओं की उन्नती तथा अवनति ये ग्रंथ लिखा हैं। मनु कहता है कि वेद पढ़ के मैने स्मृति लिखी है। इसलिए सब स्मृति ये श्रेष्ठ हैं। धर्म शास्त्र है " वो कहता के महिला ने सिर्फ सेवा करनी चाहिये।

अत्री ऋषी कहते है कि महिला तथा शूद्र ने जप, तपस्या, तीर्थयात्रा, प्रवर्ज्या, संन्यास, मंत्र साधना और देवता वो कि आराधना की तो उनका पतन होता है। मनु कहता है कि महिलाओं को कभी स्वतंत्रता देनी नही चाहिए। बचपन में उनका संरक्षण उनके पिता करते है, युवा अवस्था में पति करता है और बुढ्ापे में बच्चे करते है मनु कहता है के महिला का स्वभाव चंचल होता है। उन्होंने हमेशा खुश रहना चाहिये और घर में बर्तन मांजना चाहिये स्त्री, पुत्र, दास इन्होंने अपराध किया तो रस्सी से बांधना चाहिये और बास मारना चाहिये मनु कहता है के महिलाओं को धार्मिक संस्कार करने का अधिकार नही है। महिलाओं ने यज्ञ किया तो पण्डितों ने जाना नही चाहिये पति कैसा भी रहा ,तो भी पत्नी ने उसकी पूजा करनी चाहिये। वो कहता है के पति अपने पत्नी को घर से बहार निकल सकता है। पति पत्नी को बेंच सकता है। पति के निधन के बाद उसके पत्नी को चित्ता में मरना चाहिये। स्त्री अवगुणी होती है। पति उसको जुआ मे हर सकता है। वो पत्नी को कभी छोड़ सकता है। महिला को प्रशासन से दूर रखना चाहिये महिला अपने पिता को मुखअग्नी नही दे सकती।

महिलायें पाप योनि से उत्पन्न होती है। महिलाओं को वर्ण नही होता। शादी के बाद महिला का गोत्र बदलता है। महिलाओं को पिता का दाह संस्कार करने का अधिकार नही। महिला को पति से अलग होने का अधिकार नही स्त्री, पुरुष, दास इनको धन–संपति का अधिकार नही पुरुषों को अनेक विवाह करने का अधिकार हैं। स्त्री, वैश्य, शूद्र, क्षत्रीय, इनका वध छोटा पाप हैं।

तुलसीदास कहते है कि, ढोल, गवार स्त्री, शूद्र तथा पशु को पीटना चाहिये इसी के वजह से महिलाओं का मानसिक, बौद्धिक विकास खत्म हुआ। इनको भोग दासी बनाया गया। दक्षिण भारत में लड़की की शादी ईश्वर के साथ की जाती थी उसे देवदासी कहते है। उसका शोषण पुजारी तथा दूसरे लोंग करते है। इस तरह महिलाओं का शोषण होता है। अनेक बादशाह, तथा राजाओं की अनेक पत्नियां थी। उनके जमाने में भी महिला गुलामी मे थी।

बाबासाहेब डॉ. अंम्बेडकर कहते है कि महिला अवनति के लिये मनु जिम्मेदार है प्रो म्याक्समुलर कहते है कि, बौद्ध धर्म ने हर व्यक्ति को स्वातंत्रता और प्रगति करने का अधिकार दिया है। भारतीय इतिहास साक्षी हैं कि वैदिक कानून आखिर टूट गया। भगवान बुद्ध की प्रज्ञा शील करुणा और अहिंसा तत्वों से प्रभवित हो कर सभी ब्राम्हण, ओ.बी. सी,एस.सी,एस.टी,एन.टी. और सभी महिलाओं ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म यह जाति नही हैं। यह एक मानवतावादी तत्व ज्ञान हैं इसिलिये बाबासाहेब डॉ.अंम्बेडकर बौद्ध धर्म का स्वीकार किया।

बाबासाहेब डॉ. अंम्बेडकर जी ने भारतीय सविंधान द्वारा मनु का कानून नष्ट किया। बाबासाहेब डॉ. अंम्बेडकर ने सभी नागरिक तथा महिलाओं को कानून द्वारा धारा 14 के मुताबिक सभी को कानून के सामने समान बताया। सबसे पहले मा. ज्योतिबा फुले इन्होंने भारत में सभी के लिये पाठ्शालाएं शुरु किए सभी को पढ़ाना शुरु किया, महिलाओ को भी पहली बार पढ़ाना शुरु किया। छत्रपति शाहू महाराज ने कोल्हापूर राज्य में आरक्षण शुरु किया। सविंधान द्वारा सभी को स्वतंत्रता , समता, बंधुता और न्याय दिया गया है । धारा 17 के मुताबिक छुआछुत को नष्ट किया है। धारा 21,22 के मुताबिक सभी भारतीय और महिलाओं को भाषण, लेखन तथा व्यवसाय करने की आजादी दी है।

किसी भी महिला तथा नागरिक को जाति, वंश, लिंग तथा निवास के अधार पर भेदभाव नही किया जा सकता। महिला तथा बालक और नागरिक का शोषण नही किया जा सकता। महिला तथा सभी नागरिकों का कल्याण होना चाहिये इसीलिए संविधान ने मार्गदर्शक तत्व बताये हैं। महिला तथा सभी नागरीको धारा 25 के मुताबिक धार्मिक स्वातंत्रता दिया है। भारत के संविधान के वजह से इंदिरा जी गांधी प्रधान मंत्री बनी थी और प्रतिभा ताई पाटिल भारत कि राष्ट्रपति बनी थी। विजयलक्ष्मी पंडित युनो कि अध्यक्ष बनी थी। भारत के इतिहास मे सात सॉ साल पहले रजिया सुलताना तक्त पर बैठने वाली पहली महिला थी। भारतीय संविधान के वजह से अनेक महिलायें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश, विधायक तथा प्रशासकीय अधिकारी बनी है। महिलाओं को प्रशासन मे आरक्षण दिया गया है। भारत का संविधान सर्व श्रेष्ठ राष्ट्रीय ग्रंथ है।

हिन्दूकोडबिल

बाबासाहेब डॉ. अंम्बेडकर जी ने भारत के सभी ब्राम्हण, ओ.बी.सी, एस.सी,एस.टी,एन.टी.बौद्ध, जैन, सिक्ख, लिंगायत इनके लिये हिंदू कोडबिल बनाया ये कानून के मुताबिक महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति अधिकार दिया है, तथा महिलाओं को गोद लेने का अधिकार दिया है, महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार दिया है। महिलाओं को पति से विभक्त होने का अधिकार दिया है। महिलाओं को अंतर जातिय विवाह करने का अधिकार दिया है। दूसरा विवाह करने का किसी को अधिकार नही है, और यही कानून मंजूर करने के लिये बाबासाहब ने सभी महिलाओं के कल्याण के लिये कानून मंत्री पद का त्याग किया था। बाबासाहब के त्याग से और कार्य के सभी समाज की महिलाओं की प्रगति हुई हैं। सभी महिलाओं को चाहिये कि वे अंधश्रद्धा और विषमता का विरोध करें और विज्ञानवाद तथा मानवतावाद के रास्ते पर चले।

न्या. सुरेश घोरपड़े,
पूर्व न्यायाधीश
9021414204

***

डॉ. उदित राज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल

12 मार्च, 2015 को भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई। गत् वर्ष भाजपा में शामिल होने के पश्चात् तुरंत प्रभाव से तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री राजनाथ सिंह ने डॉ. उदित राज जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया था। अब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ज्ञात रहे कि भाजपा की इसी कार्यकारिणी द्वारा पार्टी के अहम् फैसल लिए जाते हैं।

+++

Include Dalits in the development cycle

The Centre must pass a stringent Law that punishes those who misuse funds meant for the underprivileged

25. February .2015

Reservation for the Dalits in jobs and politics is not the main way to uplift them economically; rather, it is a representation in a diverse society to keep the bonds of nationalism strong.

The Schedule Castes and Schedule Tribes constitute 25% of India's population and there have been policies to allocate resources proportionate to their population. The Centre and states are responsible to protect, promote and develop them on par with others.

When the government realised that despite many welfare schemes, the Dalits and tribals have not benefited from the Five Year Plans (FYPs) as other communities have, the Planning Commission introduced the Tribal Sub-Plan (TSP) in 1974-75 and the Scheduled Caste Sub-Plan (SCSP) in 1979-80. The idea behind these sub-plans was to set apart a sum in the budgets of each ministry in proportion to their population. At present, not only are the Dalits and Tribals being denied their share in budget allocation, but whatever funds are disbursed are either diverted or unutilised.

The pattern of denial of allocation of funds under the SCSP/TSP reveals a discriminatory attitude. In the past three FYPs — the 10th, 11th and the last three financial years under 12th — a huge amount has been curtailed. In the financial year (FY) 2002-03, the total plan expenditure was Rs 71,569.41 crore, out of which only Rs 305.73 crore was allocated for the SCSP/TSP — it should have been Rs 17,462.94 crore. In the 11th FYP, denial under the SCSP/TSP in 2007-08 was Rs 13,307.8 crore and this has increased to Rs 26,327.89 crore in the FY 2013-14.

The tragedy also persists in the realm of utilisation. In 2012-13, the budgetary allocation under the SCSP/TSP was Rs 37,113.03 crore and the unutilised amount was Rs 3,952.09 crore. The allocation is more of a notional nature than targeted. The argument is that schemes in the ministries cannot be separated for the SCs/STs and for others. It is calculated at 16.2% shown under 789 minor heads. These figures are taken as allocation, without the actual flow of funds for them. On an average, 70-75% of funds utilised are non-targeted. If critically examined, it shows that the major expenditure is incurred on survival of the SCs/STs. The total amount under the SCSP/TSP in 2013-14 was Rs 41,561.13 crore, out of which Rs 28,261.57 crore was on survival — about 68%. Of the remaining, 20% was on development, 11% on participation and 1% on protection. Some of the states violate the utilisation norms and divert the funds to other schemes. In Odisha, Rs 40.51 crore was diverted for national highways and other purposes. In Uttar Pradesh, Rs 14.41 crore was diverted for staff training at the ITI Aliganj, Lucknow.

The schemes for the Dalits and Tribals' development are not updated according to the changing needs. Implementing agencies give excuses and nodal officers are not usually designated. There are no separate cells in the ministries which can plan, monitor and coordinate. In the HRD ministry there is a team of 40 experts to supervise the Sarva Shiksha Abhiyan, but why not for the sub-plans? For the implementation of the SCSP/TSP there is an urgency to have monitoring cells at all levels comprising experts and people from the community.

The Union finance minister should look into this. Andhra Pradesh was the first state to legalise the SCSP/TSP, which means that funds allocated in this sub plan cannot be diverted. A stringent law is needed to punish those who misuse these funds. How can the cause of nationalism be espoused unless every section is included in the development cycle? Had there not been reservation and schemes to ameliorate the Dalits and tribals, they would have been languishing in every sphere, and at present, where there are no safeguards, they are excluded, like in the media, industry, share market, IT, etc.[Udit Raj is an MP from North-West Delhi.

The views expressed by the author are personal]

(Courtesy - HINDUSTAN TIMES)

NDA follows UPA in starving dalits, tribals of funds

The Narendra Modi government appears to have continued where the Congress regime left off as far as welfare of Dalits and adivasis is concerned.

Plan allocation for schemes under various ministries and departments that serve Dalits and adivasis remains much below the targeted levels in the Union Budget for 2015-16.

Total Plan allocation in the recently presented Union Budget is Rs 4.65 lakh crore. To ensure that Plan funds reach Dalits and adivasis, an executive policy of allocating 16.6% of this for Dalits under the Schedule Caste Sub Plan (SCSP) and 8.6% for tribals under the Tribal Sub Plan (TSP) has been in place since the mid-1970s.

However, the budget for 2015-16 has allocated only 6.6% for the welfare of Dalits and only 4.3% for tribals. Various Dalit and tribal advocacy groups have expressed shock over this.

READ ALSO: Govt doesn't allocate plan outlays for dalits, adivasis

While the practice of under-allocation to these two most vulnerable sections of Indian society has been going on for many years over successive governments, this time round the allocations are particularly low.

The Union government is explaining this by saying that some of the slack will have to be picked up by the state governments because more funds have been given to them than before, guided by the 14th Finance Commission.

Allocations made under the two schemes or sub-plans are meant to be used for economic development, community development through basic infrastructure and social development by attending to educational, health and other basic needs.

In the budget for 2015-16 presented to the Parliament by finance minister Arun Jaitley on 28 February, allocations for Dalits are pegged at Rs 30,850 crore, while the allocation for adivasis is only Rs 19,980 crore.

If the guidelines for these schemes were to be followed, the allocations should have been Rs 77,236 crore towards SCSP and Rs 40,014 crore towards TSP. So, Dalits have lost out on about Rs 46,386 crore and adivasis about Rs 20,034 crore.

"Prime Minister Narendra Modi had promised to whip the budget into shape and make the economy fairer for Dalits, adivasis and other marginalized sections. Unfortunately, his words have not translated into action," says Paul Divakar of the National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR).

"Allocations in the education sector have also declined to Rs 10,194.7 crore under the SCSP and Rs 5,486.44 crore under TSP. Allocation in the critical Post Matric Scholarship Scheme for SC/STs has been reduced from Rs 1,904.78 crore to Rs 1,599 crore. Retrogressive allocations are also seen in the Sarva Shiksha Abhiyan, midday meal scheme and in higher education for SCs and STs," he added.

Earlier analysis done by the NCDHR had shown that in the last eight years, Dalits have been deprived of Rs 198539.10 crore while adivasis have lost Rs 84916.42 crore through under-allocation of funds in SCSP and TSP. Even the truncated allocation is not spent completely as shown by a comparison of budget allocation and revised estimates for last year presented in this year's Union Budget.

Last year, Rs 50,548 crore was allocated unde the SCSP but only Rs 33,638 crore is provisionally estimated to have been spent. That means about a third of the funds were not spent. Similarly, Rs 32,387 crore was allocated for tribals under TSP but only Rs 20,536 crore was spent according to revised estimates. So, about 37% was unspent.

Paul Divakar N.
+91 99100 46813

SC/ST/OBC Confederation Holds State Conference

Jammu 22.02.2015 : All India Confederation of SC/ST/OBC Organizations (J&K) holds State Conference at Jammu in which employees from State, Central, financial along with social leaders participated. In the Conference newly elected MLA's/MLC's from Reserved

categories were felicitated with garlanding and presented shawls by the members of the Confederation. These legislators included Sh.Dina Nath Bhagat, Ch. Qammar Hussan, Ch. Gani Kohli, Janab Inayat Ali, Janab G M Saroori, Janab Abdul Rashid Dar, Janab Gulam Nabi Monga. All the MLA/MLC thanked the Confederation for felicitating them and assured them that they will look forward fro protecting the Constitutional provision laid down for the down trodden. Prominent among those who joined felicitation function of the MlA/MlCS were Raj Kumar Bhagat, Secretary Govt of J&K Govt. Asger Ali DCP, Naresh Langeh, Prem Nath, DD Gorka Chief Engineers, Mohan Lal Bhagat SSP, Ramesh Meenia,Gagan Joyti, S P Manhas, Ramesh Bhasin, Rafiq Khan, Des Raj Bhagat, N D Khawaja,Bachan Bhagat, Supt. Engineers, M L Kaith SP, Ankush Hans, BDO, Dr Manmeet, Tehsildar, Arun Bangotra Principal, Dr.Pawan, Dr Manohar, Dr Vijay Attri, Roshsn Din Choudhry, Mohd Abdullha, K K Thapa, Sadiq Azad, Ch.Taz, Balvinder Kundal,Xens, Tarsem Lal SDO, Mohd Arshad, Gulam Abbas, Roshan Choudhry, Slah Mohd, Kamraj Kaila, Nazir Ch. While addressing the Conference and especially newly elected legislator, State President Confederation, Sh. R K Kalsotra greeted all legislators on becoming MLA/MLC's and prayed for their bright tenure and also to give their best for the society. Kalsotra apprised them that down trodden masses have high hopes from them for full filling their Constitutional demands like Maintenance of Roster, Nullifying Catch Up Rule, Strict compliance of seniority as per fix slot for Promotion, Reservation in Temporary posts, Reservation in admission vis-à-vis scholarship, hostel facilities at Tehsil level, Representation in PSC and SSRB, Provision of SCP/STP, Extension of National Commission for SC, ST and for OBC, Reservation in High Court, Implementation of 27% Reservation for OBC's, Devising the mechanism for redressal of atrocities, State Citizenship Rights for West Pakistan Refugees /Valmiki community, Political Reservation for ST's & stop further diluting ST Status. Kalsotra apprised the participants and legislators that they will meet again on 14th April on the celebration of Baba Sahib Dr Ambedkar birthday in a large numbers. He appealed them to mobilize the masses for participation. He said that if found necessary Confederation will go for assembly gherao to meet these demands for which he requires moral support from legislators. Others who shared their views were Rohit Verma, B L Bhardwaj, Labha Ram Gandhi , Sham Basson, Mustaq Badgami, M R Bangotra, Ajit Singh Adyial, Tej Ram Dogra Ramesh Sarmal, Hurdutt Saryara, Mustaq Veere, Ramesh Kaith, Savar Ch, Pankaj Khobragade and others

+++

चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) में परिसंघ की जिला कार्यकारिणी गठित

31 जनवरी, 2015 को महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले की अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष, श्री सिद्धर्थ भोजने की उपस्थिति में श्री जयदास संगोडे (मो. 9764646479,940332533) की अध्यक्षता में पुनर्गठित हुई, जिसके पदाधिकारी निम्नवत् हैं :–

पद	नाम
जिलाध्यक्ष	श्री जयदास सांगोडे
कार्याध्यक्ष	श्री अशोक नळे
जिला महासचिव	श्री साईनाथ चांदेकर
कोषाध्यक्ष	श्री नागेश सुखदेवे
ज्येष्ठ उपाध्यक्ष	श्री रमेश शंभरकर
उपाध्यक्ष	1. श्री संजीव पथोर्डे
	2. श्री शरद रामटेके
	3. श्री राजकुमार अल्लेवार
	4. श्री सुदर्शन कांबळे
	5. श्री अरविंद उघडे
	6. श्री संतोष जिरकूंटकार
अतिरिक्त महासचिव	1. श्री अब्दुल नासिर कुरेशी
	2. श्री शेषराव वानखेडे
	3. श्री प्रफुल गेडाम
	4. विशाखा घोनमोडे
	5. श्री चानकुमार खोब्रागडे
महासचिव	1. श्री संतोष वासुदेव कुभरे
	2. श्री दिनेश कवाडे
	3. श्रीमती सिंधुताई वन्सोड
	4. श्री दिवाकर येरमलवार
कार्यालय सचिव	श्री रोशन खोब्रागडे
प्रसिद्धि प्रमुख	श्री प्रेमदास बोरकर
विभाग अध्यक्ष	
शिक्षक संगठन	श्री विनोद लाडगे
पशुसंवर्धन संघटन	डॉ. एस.बी. रायपुरे
अरोग्य विभाग	श्री प्रकाश वाघमारे

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 18 ● Issue 8 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 1 to 15 March, 2015

THE PRIME MINISTER'S SUIT

Dr. UDIT RAJ

The Prime Minister wore a nice suit and it became an issue of public debate. Even Rahul Gandhi unexpectedly entered this debate. The Prime Minister's personality traits – how he sits, the way he talks and behaves in public leave a deep impression on peoples' minds. If people in public life remain simple then the public understands and accepts them better. Unwittingly, people in public life have to enact some 'drama'. Some people are expert in this art. The Dalit Samaj has been deprived of resources for thousands of years and social crusaders engaged in the development of the Samaj wore Ambedkarite suits, pants and tie. Influenced by this, the aspiration for education and self-respect awakened in Dalits.

We were pained when people speculated about the cost of the Prime Minister's suit. No other society has such negative thinking as ours even though we are the world's third largest economy in Purchasing Power Parity **(PPP)** terms with 130 crore of the world's people.

I have always thought that had Gandhiji not been half-naked, the country might have progressed more. What a leader eats, drinks and wears is copied by his followers. That is the reason our social and political workers developed the idea of wearing more. Any social and political person would wear Khadi publicly, whatsoever his resources, but perhaps the same person would not hesitate to wear costly garments in his personal life.

Begging is seen as a "profession" only in our society. Can begging be a respectable profession? This is the reason we could not inculcate the habit of hard labour and increase production, so that facilities could also increase. Societies that did not have such ideas were able to increase production for a higher standard of living, and to develop their techniques and facilities for a better life. We have imported facilities like cars, ACs, mobiles, etc. The maiden attempt by our Prime

Dr. Udit Raj

Minister to send a similar message to the nation and to the world was misconstrued and generated a controversy that ultimately harmed society.

Foreigners have viewed India as a nation of snake charmers and jugglers. This image has waned only slowly, and the time has come to give a signal to the world that we are no less than anybody else. Barring a few exceptions, most of our leadership has preferred fine clothing. The Communist Revolution brought about a sea change in the world and the amenities that used to be the sole privilege of the masters, i.e. sources of

production, were made available to the common people. This left a lasting impression on the psyche of the poor of those countries, and changed their standard of living.

We could easily understand this phenomenon by observing the dress of Karl Marx, Engel and Lenin, et al. The harbinger of the Chinese Revolution, Mao Tse Tung, presented the same example before his country. Fidel Castro of the Cuban Revolution did the same. Great leaders like George Washington and Abraham Lincoln who laid the foundation of the United States of America were always well dressed.

One may argue that if people are poor, how can their leader be different from them? The answer to this misconception is that the leader should be an ideal person to be followed by the people. If the leader appears in a good dress, his followers will copy him and when they choose to do so, their mindset would certainly change. The people's psyche does leave an imprint on the socio-economic and political arenas. If the attire of our Prime Minister was better than that of Barack Obama, it is a matter of pride for us.

After independence, all socialist or communist leaders have mainly worn simple attire. A simple Dhoti-Kurta or plain trousers became their trade-mark. It did not matter what clothes they wore, but that did make an impression on their followers and on the people. If this culture of simplicity is called it may not be any exaggeration. They fought a battle for equitable distribution of natural resources, whatever they may be, but the psyche of the people did not change. The beneficiaries did not work hard, did not even try to secure the rights that were given to them by the Constitution. This is the reason they continued demanding more and more rights, but did not try to increase production for their own betterment.

Their exploitation by land owners cannot be ruled out, but the workers and the tillers were unable to inculcate the habit of hard work and productivity which is prevalent in other societies of the world. As a means of protest, Japanese workers increased production by increasing their working hours. Did we ever do such a thing?

People in public life have started celebrating marriages, birthdays or holidays stealthily, owing to the fear created by the paparazzi. They are compelled to lead a dual life. Some people have even started celebrating such events in foreign countries, for fear of being criticized by their countrymen.

It is not difficult to roughly calculate the expense on resources by people in public life like MLAs, MPs, Ministers, leaders and their staff. If a person appears in rags, he is praised for his or her simplicity, while the fact is that there is hardly two percent of earnings is spent on fine clothing and lodging. When broken rice was served in Bihar Chief Minister Shri Lalu Prasad Yadav's family marriage, it became a matter of discussion in far-flung areas.

All this leads to the conclusion that one must look bedraggled in public life, but do whatever one wants to do in private and thus keep the public happy. The fact that our Prime Minister wore a good suit should be lauded because he is an ideal person and the common man would be influenced by the example of his life and would strive to do better in his own life.

What message do we want to give to the people by raising the question of his costly suit? Should the people of this country march towards **or productivity?**

****

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya